

राहुल की समूची राजनीति ओ.बी.सी. दलित और अल्पसंख्यकों पर केन्द्रित है

इसलिए वे आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाना चाहते हैं

रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर भाजपा के गृहमंत्री तथा सरकार में न. दो अमित शाह ने जिस तरह डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का अपमान किया है, उस पर कांग्रेस एक विस्तृत राष्ट्रव्यापी और तृप्तानी हमला करने की योजना बना रही है। इस सिलसिले में, प्रैस कॉन्फ्रेंस होगी, धरने होंगे, विरोध प्रदर्शन होंगे तथा उसके बाद, सी.डब्ल्यू.सी. की मीटिंग होगी, जिसमें इस पर तथा अन्य मुद्दों पर आगे की योजना बनाई जायेगी।
संसद में विरोध प्रदर्शन वाले दिन, भाई-बहन (राहुल और प्रियंका गांधी) नीले रंग के वस्त्र पहने हुये थे, जो दलित-उत्थान का प्रतीक है। इसी रंग के वस्त्र अम्बेडकर तथा काशी राम पहन कर रहे थे, जो दलितों को सशक्त बनाकर, उन्हें राजनैतिक मुख्याधार में लाये थे।

- कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई वरिष्ठ नेता और ए.आई.सी.सी. के मध्यम दर्जे के नेताओं में राहुल गांधी की राजनीति को लेकर काफी बेचैनी है। इन नेताओं को लगता है कि इससे सर्वग्नोट पार्टी से पूरी तरह विमुख हो जायेंगे।
- इन नेताओं का कहना है कि दलितों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, इन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया है, जैसा हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ था।
- कांग्रेस के सर्वग्नोट नेता व कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल सवर्णों, ओ.बी.सी., दलितों व अल्पसंख्यकों के बीच संतुलन बिठाएं, पर लगता है राहुल उनकी नहीं सुन रहे हैं।

इसके अलावा, उनका जोर दलितों का जोरदार समर्थन करने पर होगा। राहुल की पूरी राजनीति अब ओ.बी.सी., दलितों तथा अल्पसंख्यकों पर केन्द्रित है और वे चाहते हैं कि आरक्षण बढ़कर, 50 प्रतिशत को पार कर जाये।
सी.डब्ल्यू.सी. के बहुत से वरिष्ठ नेताओं के साथ, मध्यम श्रेणी के नेताओं में राहुल गांधी को इस राजनीति को लेकर काफी बेचैनी है। उनका मत है कि यह नीति ऊँची जातियों को कांग्रेस से बिल्कुल दूर कर देगी, तथा दलितों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, जैसा हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ।
कांग्रेस के ऊँची जातियों के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल संतुलन बनाये रखें, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल उनकी नहीं सुन रहे हैं।

एल.पी.जी. टैंकर ब्लास्ट में हाई कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया

जयपुर, 21 दिसम्बर राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांक्रोटा के पास एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की घटना पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही, अदालत ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय, पेट्रोलियम सचिव और मुख्य सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है।
वहीं, अदालत ने प्रकरण को जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई के लिए संबंधित खंडपीठ के समक्ष दस जनवरी को सूचीबद्ध करने को कहा है। अदालत ने इस मुद्दे पर केन्द्र और राज्य सरकार

केन्द्र व राज्य सरकार से इस मुद्दे पर उठाये गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी।

से उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है। जस्टिस अनूप कुमार डंड को एकलपीठ ने यह आदेश दिया।
अदालत ने केन्द्र और राज्य सरकार से बताने को कहा है कि क्यों न इस हादसे के दोषी अफसरों के खिलाफ जांच कर इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाए वहीं, अत्यधिक ज्वलनशील रसायन व गैस के गोदाम आदि को घनी आबादी क्षेत्र से दूर किया जाए। अदालत ने अधिकारियों से यह भी पूछा है कि क्यों न पुलों एवं ओवरब्रिजों के निर्माण कार्यों को तय समय में पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएं और ज्वलनशील गैस व रसायनों के परिवहन के लिए एक पृथक रास्ता सुझाए जाने पर भी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए।
अदालत ने केन्द्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को बताने को कहा है कि क्यों न घटना के मृतकों, घायलों (श्रेष्ठ पृष्ठ 7 पर)

आप और जद (यू) के बीच छिड़ा शब्द युद्ध

अंबेडकर के मुद्दे पर केजरीवाल की चिट्ठी से भड़की जद (यू)

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर। अंबेडकर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह की "अपमानजनक टिप्पणियों" को लेकर भाजपा तथा उसके दो प्रमुख सहायक दलों, तेलगू देशम पार्टी (टी.डी.पी.) तथा जनता दल (यू) के बीच दरार पैदा करने की अरविंद केजरीवाल की चाल के बाद, दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है।
शाह की टिप्पणियों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच, आम आदमी पार्टी के कन्वीवर अरविंद केजरीवाल ने टी.डी.पी. चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि संविधान के निर्माता के विरुद्ध गृह मंत्री अमित शाह की अपमानजनक टिप्पणियों के बाद उन्हें अपने आपको भाजपा से अलग कर लेना चाहिए।

- जद (यू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि एक भ्रष्ट पार्टी को कुमार जैसे नेता को सलाह देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने केजरीवाल पर दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं देने का आरोप लगाया।
- केजरीवाल ने अंबेडकर पर शाह की टिप्पणी के खिलाफ जद (यू) प्रमुख व तेलगू देशम प्रमुख को पत्र लिखा था और भाजपा से गठबंधन तोड़ने की अपील की थी।
- इस मुद्दे पर जहाँ तेलगू देशम ने चुप्पी साध रखी है वहीं जद (यू) ने आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला।

का समर्थन नहीं कर सकते, जिसने अंबेडकर का अपमान किया है।
जद (यू) वर्किंग प्रैसिडेंट तथा राज्यसभा सदस्य, संजय झा ने पलटवार किया तथा केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। झा ने कहा कि "भ्रष्टाचार के आरोपों" से दूषित पार्टी को नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को सुझाव देने का अधिकार नहीं है।
झा ने केजरीवाल पर, हाशिए पर पड़े अधिकार विहीन वर्गों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आप ने दलित और पिछड़े वर्गों के एक भी नेता को राज्यसभा में नहीं भेजा। उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि दलित नेता को पंजाब का उपमुख्यमंत्री बनाने का अपना वादा भी केजरीवाल ने पूरा नहीं किया।
झा ने आगे कहा, नीतीश कुमार ने 2014 में महादलित जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने कहा कि इण्डिया ब्लॉक के साथ गठबंधन के समय नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था और यह भी कि ब्लॉक के अन्य पार्टनरों से उन्हें इस मुद्दे पर बहुत कम समर्थन मिला था।
झा ने यह भी कहा कि दो दलित मंत्रियों ने केजरीवाल के मंत्रिमंडल से यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि उनके लोगों के हितों की अनदेखी की जा रही थी। झा ने कहा कि "2020 में, जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी, उस समय केजरीवाल ने बिहार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जबकि उस आपदा के समय नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों के लिए हर तरह के इंतजाम किए थे।"

क्रेडिट कार्ड बकाया के भुगतान से 30 प्रतिशत ब्याज की सीमा हटाई सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के नैशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीट्रैसल कमीशन के आदेश को रद्द किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीट्रैसल कमीशन के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बैंकों को क्रेडिट कार्ड के बकाया या 30 प्रतिशत ब्याज वसूली की सीमा लगाई गई थी। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चन्द शर्मा की बेंच ने आयोग के 2008 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत कहा गया था कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स से बकाया पर 30 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज वसूलना गलत ट्रेड प्रैक्टिस है।

- रिट्रैसल कमीशन ने 2008 के फैसले में क्रेडिट कार्ड बकाया के भुगतान पर 36 से 49 प्रतिशत ब्याज वसूली को सूद खोरी बताया था और ब्याज की सीमा 30 प्रतिशत तय कर दी थी।
- कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर बैंकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग का फैसला पलट दिया।
- इस फैसले से ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, अगर उन्होंने निर्धारित समय पर क्रेडिट कार्ड का बकाया नहीं चुकाया तो।

'वाहनों के अवधि पार फिटनेस नवीनीकरण में अतिरिक्त फीस अवैध'

जयपुर, 21 दिसम्बर राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मशिवल वाहनों के अवधि पार फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण के लिए पचास रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त फीस वसूलने के प्रावधान को कानून की नजर में गलत मानते हुए, उसे अवैध घोषित कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने कहा है कि

- वाहनों पर अवधि पार नवीनीकरण में 50 रुपये प्रतिदिन की अतिरिक्त फीस वसूलने के प्रावधान को अवैध घोषित किया।

याचिकाकर्ताओं से फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए देरी के आधार पर अतिरिक्त फीस वसूल नहीं की जाए।
चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने ये आदेश श्याम प्रकाश मीणा व 195 अन्य याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल और अधिवक्ता रजनी व्यास ने अदालत को बताया कि केन्द्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत, 4 अक्टूबर, 2021 को (श्रेष्ठ पृष्ठ 7 पर)

और क्या रिजर्व बैंक को, बैंकों/गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों/पेसा उधार देने वालों को किसी विशिष्ट ब्याज दर से अधिक ब्याज लेने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करना चाहिए।
रिजर्व बैंक ने कहा कि हालांकि उसने बैंकों को निर्देश दिया है कि जरूरत से ज्यादा ब्याज दर न ली जाए, लेकिन उसकी नीति ब्याज दरों को नियंत्रित करने की नहीं है। इसलिए यह मामला बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुपुर्द कर दिया गया है। इसलिए आर.बी.आई. को निर्देश जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत एक विवेकाधीन शक्ति है।

'24 दिसम्बर को देश भर में अंबेडकर के सम्मान में और शाह के खिलाफ प्रदर्शन होगा'

कांग्रेस और बसपा ने अपने-अपने कार्यक्रम घोषित किए

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने आज घोषणा की कि बाबा साहेब अम्बेडकर पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की हाल ही की टिप्पणी को लेकर 24 दिसम्बर को पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन किया जायेगा।
जहाँ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने घोषणा की है कि संसद में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में 24 दिसम्बर को देशव्यापी प्रदर्शन किया जायेगा, वहीं कांग्रेस महासचिव तथा संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी का विरोध-प्रदर्शन, जिसमें शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जारी रहेगा तथा वे (कांग्रेस) "मनुस्मृति-पूजकों" के विरोध में, अम्बेडकर की विरासत की सुरक्षा के लिये संघर्ष करेंगे।
मायावती ने कहा, "अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान करके, जनता

- कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने अंबेडकर सम्मान सप्ताह मनाने की घोषणा करते हुए कहा, मनुस्मृति के उपासकों के खिलाफ अंबेडकर की विरासत को बचाने के लिए और शाह का इस्तीफा मांगने के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
- मायावती ने एक्स पर कहा, हमने कहा अमित शाह माफी मांगें और अपने शब्द वापस लें, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए हम 24 दिसम्बर को देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
- कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि 22 और 23 दिसम्बर को कांग्रेस के सभी नेता सांसद अपने क्षेत्रों में प्रैस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 24 दिसम्बर को देश में अंबेडकर सम्मान मार्च आयोजित किए जायेंगे।

विरोध करने का निर्णय लिया है। उस दिन सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध एवं प्रदर्शन किये जायेंगे।
जैसी कि पहले सूचना दी जा चुकी है, कांग्रेस आगामी सप्ताह को "अम्बेडकर सम्मान सप्ताह" के रूप में मनायेगी। इसी सिलसिले में, वेणुगोपाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा है, "सभी कांग्रेस सांसद, वरिष्ठ नेता तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों तथा गृह जिलों में 22-23 दिसम्बर को प्रैस कॉन्फ्रेंसों का आयोजन करेंगे। 24 दिसम्बर को, हम सारे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर सम्मान मार्च निकालेंगे तथा जिला कलेक्टरों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, जिसमें अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जायेगी।"
वरिष्ठ कर्मि नेता ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, पद-यात्रा में सबसे (श्रेष्ठ पृष्ठ 7 पर)

स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर उत्थान आयुष्मान भारत, आयुष्मान राजस्थान

SAANS
साँस
निमोनिया नहीं, तो बचपन सही

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

सर्दी के दिनों में बच्चों का रखें विशेष ख्याल... करें निमोनिया से बचाव

सुरक्षा	रोकथाम	लक्षण
बच्चे को पहले 6 महीनों के दौरान केवल स्तनपान कराएं	निमोनिया के विरुद्ध टीकाकरण (यू-विन पोर्टल में अपडेट करें)	बुखार
बच्चों को पर्याप्त पोषण आहार (उम्र के अनुसार) प्रदान करें	घर के अंदर प्रदूषण कम करें	तेज साँस चलना या साँस लेने में कठिनाई होना

यदि बच्चे के स्वास्थ्य में ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्यकार्मिक से सम्पर्क करें

सम्पूर्ण प्रदेश में SAANS अभियान 12 नवम्बर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक संचालित है, निमोनिया रोग की पहचान, प्रारंभिक प्रबंधन, रेफरल व उपचार सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं (आई.ई.सी.), राजस्थान



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.) के माध्यम से जिला कलेक्टरों की एक बैठक ली। जिसमें बजट घोषणा के विकास कार्यों के लिए भू-आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

‘दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर शीघ्र सुधारें’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कलेक्टरों को वी.सी. से भू आवंटन प्रकरण 31 दिसम्बर तक निपटाने के निर्देश दिये

जयपुर, 21 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सड़कों के दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाना आवश्यक है। सभी जिलों में ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन किया जाए। साथ ही, सभी जिलों में परिवहन विभाग के उड़नदस्ते, अनफिट एवं बिना परमिट के वाहनों तथा ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ सघन कार्रवाई करें। इसके अलावा, यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जागरूकता अभियान भी चलाया जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सभी जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि राइज़िंग राजस्थान समिट में हुए एम.ओ.यू. को धरातल पर उतारने के लिये संबंधित विभागों के साथ समन्वय बना कर काम करें।

एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नवीन सहायक अभियंता कार्यालय के लिए भू-आवंटन को भी समीक्षा की। शर्मा ने कहा कि बजट घोषणा की अनुपालना में जयपुर में विकसित की जाने वाली हाईटेक सिटी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस संबंध में उद्योग विभाग, राजस्व विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही की जाए। इसके तहत, विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी, पानी-बिजली सहित आधारभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।

सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित, विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव उपस्थित रहे एवं समस्त जिला कलेक्टरों वीसी के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं से संबंधित भू-आवंटन के शेष प्रकरणों का त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने 31 दिसम्बर तक की अवधि में प्रकरणों के भूमि चिन्हीकरण तथा चिन्हित भूमि के प्रस्ताव संबंधित विभाग को भिजवाने एवं भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोटाही बर्दाश नहीं की जाएगी।

‘वाहनों के अवधि पार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत, वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि बीतने के बाद नवीनीकरण करने पर प्रतिदिन पचास रूपए की अतिरिक्त फीस वसूलना का प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान मोटर अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है, क्योंकि अधिनियम में पैनल्टी का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सरकार अतिरिक्त फीस के नाम पर पैनल्टी वसूल रही है। अधिनियम के तहत शुल्क लगाया जा सकता है, लेकिन फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में देरी के आधार पर अतिरिक्त फीस नहीं वसूली जा सकती। ऐसे में इस प्रावधान को रद्द किया जाए। इसका विरोध करते हुए

केन्द्र सरकार की ओर से एसजी आरडी रस्तोगी व राज्य सरकार की ओर से एसएस नरुका ने कहा कि अधिनियम के तहत उन्हें फिटनेस, लाइसेंस और परमिट आदि के लिए शुल्क लगाने की शक्ति है। अवधि पार परमिट के नवीनीकरण के लिए वसूला गया अतिरिक्त शुल्क, शुल्क संरचना का ही हिस्सा है। अधिनियम के तहत पूरी तरह से फिट वाहन ही रोड पर चल सकते हैं। ऐसे में सरकार को अतिरिक्त लेवी लगाने का अधिकार है। दोनों पक्षों को बहस सुनने के बाद अदालत ने अवधि पार प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के लिए प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त फीस वसूलने को अवैध माना है।

ई.डी. को केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिली

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुंबई में फंसने वाले हैं। उपराज्यपाल को अरविंद केजरीवाल की शिकायतों के अन्वेषण के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से दी गई है। 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। अब जाकर

‘भाजपा का बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा से कोई मतलब नहीं’

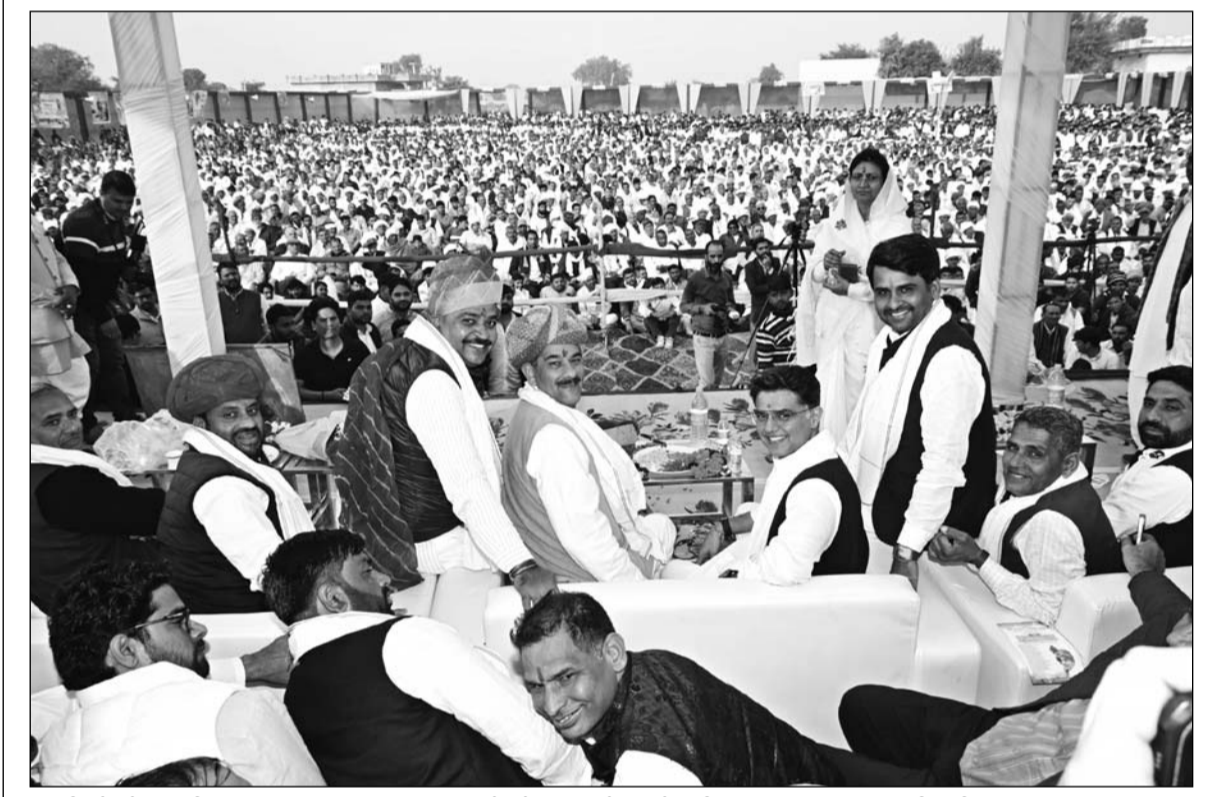
सचिन पायलट ने बहरोड़ के पास किसान सम्मेलन में भंवर जितेंद्र व जूली के साथ भाग लिया

बहरोड़, 21 दिसम्बर। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि गृहमंत्री ने अभी जो संसद भवन में भाषण दिया था, उनके घेरे की बात मुंह पर आ गई। पायलट ने जनता से कहा कि बनाने वाले भी आप हो, गिराने वाले भी आप हो। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बहरोड़ के गांव पहाड़ी की शुक्ला की ढाणी में किसान सम्मेलन में उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी विधायक उन लोगों को अगर खिसकाना है 4 साल बाद, तो हम लोगों को मिलकर बहुत घूमना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देनी पड़ेगी। वे देखते हैं, जब नेता ही भागदौड़ नहीं कर रहे, तो हम क्यों करें। आप और हम मिलकर पूरे प्रदेश में जाकर कार्यकर्ताओं को ताकत दें, हिम्मत बंधाएं।

बहरोड़ के गांव पहाड़ी में शुक्ला की ढाणी में स्वर्गीय वीरबल बोहरा व स्वर्गीय छिमली देवी की मूर्ति का अनावरण हुआ। साथ ही स्कूल में बरामदा का उद्घाटन समारोह भी हुआ। चिकित्सा से कोई मतलब नहीं है। पायलट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मंच से कहा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। आज राजस्थान में विपक्ष में है हम लोग। मोदी, अमित शाह दिल्ली से और यहां भजनलाल जी, वसुंधरा जी, सब कोई ताकत लगा रहे हैं। इन लोगों को अगर खिसकाना है 4 साल बाद, तो हम लोगों को मिलकर बहुत घूमना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देनी पड़ेगी। वे देखते हैं, जब नेता ही भागदौड़ नहीं कर रहे, तो हम क्यों करें। आप और हम मिलकर पूरे प्रदेश में जाकर कार्यकर्ताओं को ताकत दें, हिम्मत बंधाएं।

किसान सम्मेलन में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष टीकराम जूली ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि माता-पिता की प्रतिमा लगाना बच्चों का सौभाग्य है, आज के युग में जहां भाई-भाई का दुश्मन हो रहा है, ऐसे समय में ऐसे नेक कार्य समाज को नया संदेश देने और संस्कारों को जिंदा रखने तथा आने वाले पीढ़ियों को सिखाने का काम करेंगे। पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जनसमूह को संबोधित करते हुए बोले, उन्होंने रातोंरात तीन काले कानून बनाकर देश के किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया लेकिन अन्नदाता की आवाज और अपने अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई ने देश की राजधानी दिल्ली को छावनी में

तब्दील कर दिया और सरकार को चुटने के बल ला दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीब और काशतकारों को बांटने के लिए बनी है, इस सरकार को अडानी और अंबानी चला रहे हैं। देश के पीएम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि आज किसान को खाद -बीज नहीं मिल रहा, यह सरकार किसान का खून पीना चाहती है। उन्होंने स्वर्गीय राजेश पायलट को याद करते हुए कहा कि किसानों की लड़ाई में उनकी भूमिका को सदैव याद किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, विधायक ललित यादव, कांति प्रसाद मीणा, मांगीलाल मीणा, अजीत यादव, संजय यादव, आर्यन जुबेर खान, इमरान खान, रामफल गुर्जर, संजोय बरोट, हरिशंकर रावत, विश्राम गुर्जर, बलराम यादव, गणेश खान, रोहितारा चौधरी सहित, गणमान्य लोग उपस्थित थे।



पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बहरोड़ के गांव पहाड़ी की शुक्ला की ढाणी में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भाजपा ध्यान भटकाने के लिए, मंदिर- मस्जिद, हिंदू- मुसलमान, हिंदुस्तान- पाकिस्तान की बात करती है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा से कोई मतलब नहीं है।

संसद में धक्का-मुक्की पर 7 सदस्यीय एस.आई.टी. का गठन

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। संसद में हुए धक्का-मुक्की मामले की जांच अब गति पकड़ने लगी है। इस मामले को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से दिल्ली पुलिस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसकी जांच अब क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित आई.एस.सी. यूनिट करेगी। यह मामला संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्का मुक्की का है जिसमें बीजेपी के दो सांसद, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपुरा घायल हो गए थे। दोनों का इलाज आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में मामले की संजीवनी और गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार रात क्राइम ब्रांच की एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है। क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम की टीम में 2 एसपी, 2 इंसपेक्टर और 3 सब इंसपेक्टर होंगे शामिल जो सीधे सीधी फोर्मों को रिपोर्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच में 2 एसपी को एसआईटी में इसलिए शामिल किया गया है कि क्योंकि मामला पोलिटिकली हाई प्रोफाइल है।

इस प्रकरण में भाजपा के दो सांसद घायल हो गये थे। मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। क्राइम ब्रांच ने जाँच के लिये 7 सदस्यों की एस.आई.टी. का गठन किया।

दिल्ली-एन.सी.आर. में हल्की वर्षा का अनुमान

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान मानस के नीचे पहुंच रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एन.सी.आर. में हल्की वर्षा का अनुमान है।

हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड में बर्फ गिरने से सर्दी बढ़ी। दिल्ली-एन.सी.आर. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। अभी दिल्ली-एन.सी.आर. में सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट देखी जा रही है। दिन में धूप रहने के कारण लोगों को थोड़ी ठंड से राहत मिलती है। वहीं, दो दिन बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट आएगी और ठंड भी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को औसत न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

अनपैक्ट पाॅपकॉर्न पर 5, ब्रैण्डेड पर 12 प्रतिशत जी.एस.टी. वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जी.एस.टी. काउन्सिल ने 45 वस्तुओं पर टैक्स दर कम की

जैसलमेर, 21 दिसम्बर (नि.सं.)। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस से रूबरू होकर बताया कि जी.एस.टी. परिषद की 55 वीं बैठक में तय किया गया है कि अनपैक्ट पाॅपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागेगा, लेबल वाले और ब्रैंडेड पाॅपकॉर्न पर 12 प्रतिशत टैक्स लागेगा, जबकि कैरमल युक्त पाॅपकॉर्न को 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में रखा गया है। उन्होंने बताया कि जी.एस.टी. परिषद ने 1904 के तहत वर्गीकृत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफ.आर.के.) पर जी.एस.टी. दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की। जी.एस.टी. परिषद ने जीन थैरेपी पर भी जीएसटी से पूरी छूट देने की सिफारिश की। मोटर वाहन दुर्घटना निधि के लिए तीसरे पक्ष के

काउन्सिल ने जीन थैरेपी पर जी.एस.टी. से पूरी छूट देने की सिफारिश की। वाउचर के लेन-देन पर जी.एस.टी. नहीं लगाने की सिफारिश की, क्योंकि यह न तो माल की आपूर्ति है और न ही सेवाओं की आपूर्ति। वाउचर से संबंधित प्रावधानों को भी सरल बनाया जा रहा है। जी.एस.टी. परिषद ने स्पष्ट किया कि ऋण शर्तों का पालन न करने पर बैंकों और एन.बी.एफ.सी. द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए और वसूल गए ढंटात्मक

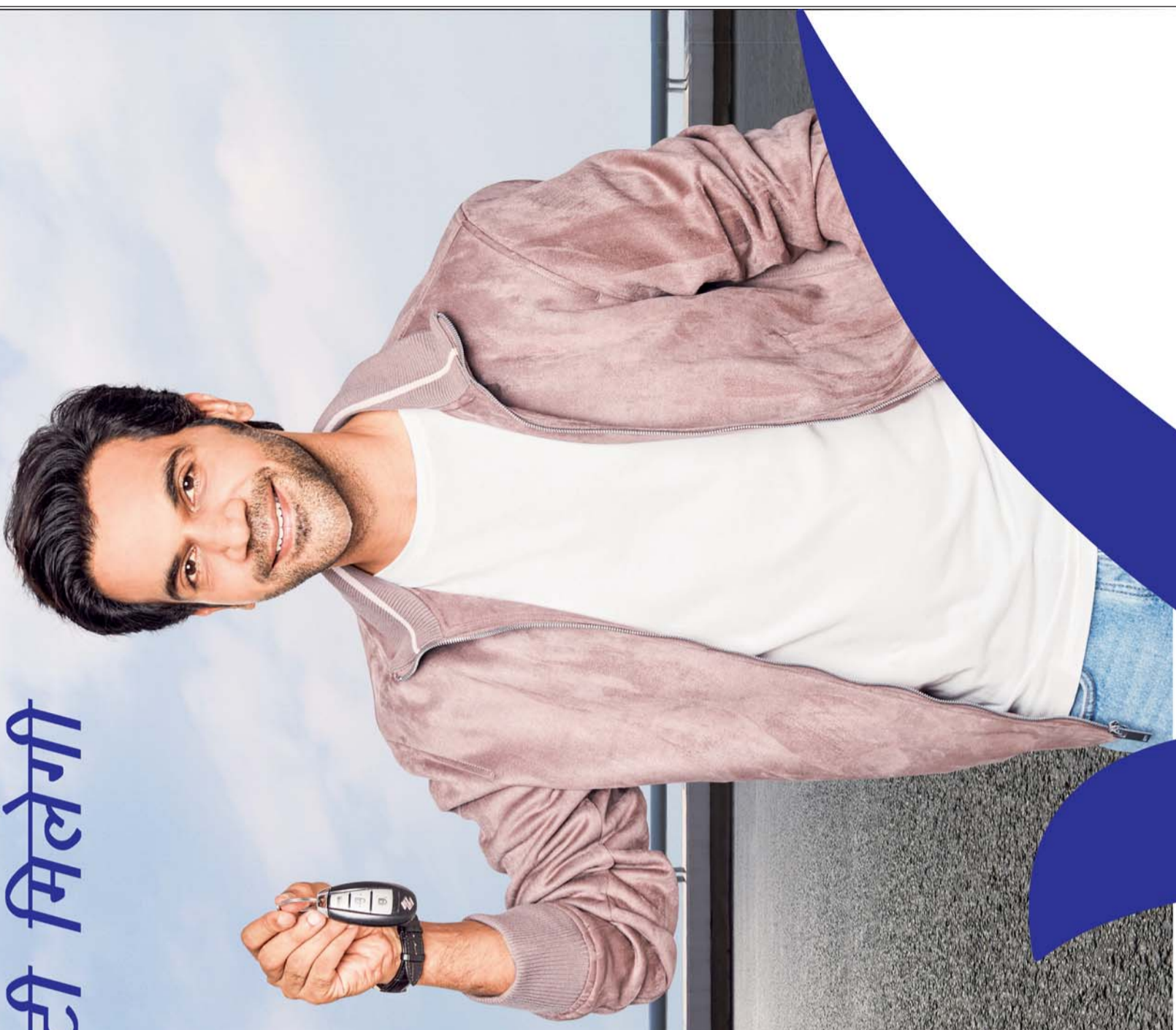
मुंबई, 21 दिसंबर। महाराष्ट्र में फंडणबीस सरकार ने मंत्रियों को विभाग आर्बिट्रर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह, ऊर्जा और कानून विभाग अपने पास रखा है, जबकि अजित पवार को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग सौंपा गया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक

महाराष्ट्र में विभाग बाँटे, अजित को वित्त व शिंदे को शहरी विकास विभाग मिला। निर्माण जैसे तीन मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, गृह विभाग उन्हें नहीं दिया गया, जिसे वह कथित तौर पर चाह रहे थे।

TRUE VALUE

वाइड रेंज के साथ बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी
सिर्फ **TRUE VALUE** पे

MARUTI SUZUKI

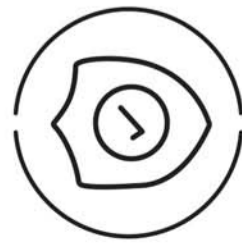


TRUE VALUE

MARUTI SUZUKI

CELEBRATING

50 LAKH+
HAPPY FAMILIES



376 क्वालिटी
चेक पॉइंट्स



3 फ्री सर्विस और
1 साल तक की वारंटी*



वेरिफाइड
कार हिस्ट्री*

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruevalue.com

*नियम और शर्तें लागू। Verified Car History और Warranty केवल True Value प्रमाणित कारों पर लागू। निःशुल्क सेवा केवल श्रम शुल्क पर लागू है। वाहन पर काला शीशा प्रकाश प्रभाव के कारण होता है।



अधिक
जानने के लिए
स्कैन करें